STD Facilities with District Headquarters of U.P. and their connection with National Dialling Grid

5743. SHRI MOHD. ASRAR AHMAD: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the district headquarters of U.P. State which are provided with direct dialling facilities and connected with National Dialling Grid; and

(b) the district headquarters which are proposed to be so connected during 1980-81 and 1981-82 in U.P.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) The following District Headquarters of U.P. have been provided with STD facilities:—

Agra, Aligarh, Allahabad, Bareilly, Bulandshahr, Dehradun, Faizabad, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Rai Bareilly, Shahjehanpur, Saharanpur, Unnao and Varanasi.

Out of these the following stations have access to National Dialling Grid on a limited basis:—

Agra, Allahabad, Varanasi, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow.

(b) The following district headquarters are proposed to be connected to National Dialling Grid:—

During 1980-81.

Bareilly, Gorakhpur, Moradabad, Shahjahanpur, Sitapur.

During 1981-82.

Dehradun, Pilibhit, Lakhinpuri Kheri, Rampur.

माडर्न ब्रेड में कील का पाया जाना

5744. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही माडर्न बेकरीज की एक यूनिट मध्य प्रदेश में इन्दौर में कार्य कर रही है;

(ख) क्या उनका ध्यान इन्दौर से प्रकाशित दिनांक 19 जून, के 'नई दुनिया' दैनिक में छपी फोटो की ओर दिलाया गया है जिसमें माडर्न ब्रेड में जंग लगी कील दिखाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन्दौर में माडर्न ब्रेड की बिक्री पर रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ और (ङ). माडर्न बेकरीज (इं.) ने सूचित किया है कि "नई दुनिया" में माडर्न ब्रेड में एक कील दिखाते हुये एक चित्र छपने के बाद उक्त यूनिट के महाप्रबंधक ने इस मामले की बारीकी से जांच की थी और वे इन्दौर यूनिट से भेजे जा रहे उत्पाद की किस्म से सन्तुष्ट थे । माडर्न ब्रेड उच्च स्तर के स्वस्थ वातावरण में तैयार की जाती है और कम्पनी का सिस्टम इतना साफ-सुथरा और स्वचालित है कि माल तैयार होने की प्रक्रिया के दौरान किसी कील के आने और स्लाइसिंग मशीन से निकलने की कोई संभावना नहीं है । कम्पनी को यह आशंका है कि माडर्न ब्रेड की साख को बिगाड़ने के उद्देश्य से किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जंग लगी कील या तो रैपर को फाड़ कर या रैपर को खोलकर और उसके अन्दर कील डालने के बाद उसे पुन: पैक कर डाली गयी हो सकती है ।

Disparity in Pay Scales of Employees in different Universities

5745. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the reasons for disparity in pay scales of hospital employees of

Kashi Hindu University and Aligarh Muslim University and those of general cadre employees;

(b) whether Government have decided to take some corrective action or set up some committee to go into this; and

(c) if so, the name and terms of references of the Committee?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) and (c). Such action as may be necessary would be taken.

भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना

5746. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **ग्रामीण पुर्ननिर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार या तो भूमि से सम्बन्धित विषय को संघ-सूची में शामिल करने या विशेष भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम पारित करके उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का है; और

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम इतने जटिल हैं कि उनसे गरीब हरिजनों और आदिवासियों को भूमि के मामले में न्याय नहीं मिल पाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारत सरकार ने अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है ताकि हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों को अभीष्ट लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके।

Government Accommodation

5747. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the number of eligible Central Government Employees in New Delhi with more than five years of service for whom no accommodation has been provided classified on the basis of length of service;

(b) the number of those with less than two years of service for whom quarters have been allotted as dependents of retired employees;

(c) whether among those in list (b) who retired from the Works and Housing Ministry have been given preferential treatment;

(d) whether Government propose to strictly adhere to seniority as the basis for house allotment; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) The number of such employees eligible for General Pool accommodation in Delhi who have applied for the same is 39,000 approximately. In the case of employees entitled to type A to type D, the priority date is reckoned from the date they are in continuous Government service and as such, in their case, the allotment is made on the basis of length of their service. In other types, the date of priority is reckoned from the date on which the prescribed emoluments are drawn and therefore, the length of service is not relevant in such cases.

(b) The concession of giving *ad hoc* allotment of Government accommodation to dependents of retired employees, who are otherwise eligible for the same was withdrawn with effect from 1-5-1978. As the length of service is not relevant for the purpose of making such ad hoc allotment, no information is maintained in this regard.